नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 175
दि. 30.03.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

LPG संकट के बीच केरोसिन की वापसी: सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल पंपों से भी मिलेगा तेल

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहे असर के बीच भारत सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए एक अहम और तात्कालिक निर्णय लिया है। घरेलू स्तर पर एलपीजी की संभावित कमी को देखते हुए अब केरोसिन (मिट्टी का तेल) को फिर से वैकल्पिक ईंधन के रूप में सक्रिय किया जा रहा है। यह कदम न केवल आपातकालीन राहत के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि वैश्विक संकट का असर अब भारत के रोजमर्रा के जीवन तक पहुंच चुका है। सरकार द्वारा 29 मार्च को जारी अधिसूचना के अनुसार, Ministry of Petroleum and Natural Gas ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 60 दिनों के लिए सुपीरियर केरोसिन ऑयल (SKO) की एड-हॉक सप्लाई को मंजूरी दी है। इसमें Uttar Pradesh, Gujarat, Haryana और Delhi जैसे बड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इस फैसले का उद्देश्य है कि आम नागरिकों को खाना पकाने और रोशनी जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए ईंधन की कमी का सामना न करना पड़े।

इस बार सबसे बड़ा बदलाव यह है कि केरोसिन की बिक्री अब केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि चुनिंदा पेट्रोल पंपों से भी की जा सकेगी। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को इसके लिए अनुमति दे दी है। हर पेट्रोल पंप पर

अधिकतम 5,000 लीटर तक केरोसिन स्टॉक रखने की सीमा तय की गई है, जबकि प्रत्येक जिले में दो पेट्रोल पंपों को इसके लिए नामित किया जाएगा। इससे आम लोगों के लिए ईंधन तक पहुंच आसान और तेज हो सकेगी।

ईंधन की सप्लाई को बाधारहित बनाने के लिए सरकार ने केरोसिन के भंडारण, परिवहन और वितरण से जुड़े नियमों में भी अस्थायी ढील दी है। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि इस ढील का दुरुपयोग न हो, इसके लिए सख्त निगरानी भी जारी रहेगी। केरोसिन का उपयोग केवल घरेलू जरूरतों—जैसे खाना पकाने और रोशनी—के लिए ही सीमित रहेगा, ताकि इसे पेट्रोल या डीज़ल में मिलाकर अवैध गतिविधियों को बढ़ावा न मिले। जहां पहले केरोसिन को धीरे-धीरे खत्म करने की नीति अपनाई गई थी, वहीं अब संकट के समय इसे दोबारा सक्रिय करना सरकार की व्यावहारिक सोच को दर्शाता है। जिन क्षेत्रों में पहले केरोसिन की आपूर्ति बंद कर दी गई थी, वहां भी अब PDS के जरिए अस्थायी रूप से वितरण शुरू किया जाएगा। इस दौरान सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और Petroleum and Explosives Safety Organisation (PESO) के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। असल में यह पूरा संकट पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव से जुड़ा हुआ है। Strait of Hormuz जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में बाधा आने से दुनिया की लगभग 20% ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होती है। भारत, जो अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इस वैश्विक व्यवधान से सीधे प्रभावित हुआ है। खाड़ी देशों से आने वाली गैस सप्लाई में अनिश्चितता के कारण घरेलू बाजार में दबाव बढ़ा है। यह स्थिति इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले एक दशक में भारत ने केरोसिन पर अपनी निर्भरता को काफी हद तक कम कर दिया था। Pradhan Mantri Ujjwala Yojana जैसी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए गए और बिजली की पहुंच बढ़ने से केरोसिन की जरूरत घट गई। इसके चलते केरोसिन की सब्सिडी और वितरण को धीरे-धीरे सीमित कर दिया गया था।

लेकिन मौजूदा वैश्विक हालात ने यह दिखा दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा केवल एक स्रोत पर निर्भर नहीं रह सकती। सरकार का यह कदम एक तरह से "बैकअप सिस्टम" को सक्रिय करने जैसा है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित संकट में आम लोगों को न्यूनतम दिक्कत हो।

इस फैसले से जहां आम नागरिकों को तत्काल राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं यह एक चेतावनी भी है कि वैश्विक ऊर्जा संकट अब स्थानीय स्तर पर भी असर डालने लगा है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि अंतरराष्ट्रीय हालात कितनी जल्दी सामान्य होते हैं और भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को किस तरह संतुलित करता है।

नेपाल सरकार का बड़ा फैसला: 15 दिनों में सभी कोचिंग सेंटर बंद करने का निर्देश

Kathmandu। शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों पर बढ़ते मानसिक व आर्थिक दबाव को कम करने के उद्देश्य से नेपाल सरकार ने एक सख्त और ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने देशभर में संचालित प्रवेश परीक्षा तैयारी कक्षाओं, ब्रिज कोर्स और निजी कोचिंग सेंटरों को 15 दिनों के भीतर पूरी तरह बंद करने का निर्देश जारी किया है।

यह निर्णय Ministry of Education Science and Technology Nepal द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के माध्यम से सामने आया। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस तरह के कोचिंग प्रोग्राम छात्रों के समग्र विकास के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं और शिक्षा प्रणाली में असंतुलन पैदा कर रहे हैं।

सरकार का मानना है कि स्कूल और उच्च शिक्षा में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही कई निजी संस्थाएं प्रवेश परीक्षा की तैयारी के नाम पर कोचिंग कक्षाएं और ब्रिज कोर्स चलाती हैं। ये संस्थान छात्रों को बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तविकता में यह प्रक्रिया छात्रों के मनोविज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। छोटी उम्र में ही प्रतियोगिता का अत्यधिक दबाव छात्रों में तनाव, चिंता और असुरक्षा की भावना को बढ़ा देता है।

इसके साथ ही, इन कोचिंग सेंटरों का एक बड़ा आर्थिक पहलू भी सामने आया है। अभिभावकों को अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद में भारी-भरकम फीस चुकानी पड़ती है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि कई जगहों

पर "कोचिंग सेंटर" के नाम पर एक तरह का शिक्षा व्यवसाय (एजुकेशन माफिया) पनप रहा है, जहां मुनाफा प्राथमिकता बन गया है, न कि छात्रों का वास्तविक विकास।

मंत्रालय ने अपने आदेश में सभी संबंधित संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे 14 अप्रैल तक अपने कोचिंग सेंटर पूरी तरह बंद कर दें। इसके बाद यदि कोई भी संस्था इस प्रकार की गतिविधियां चलाती हुई पाई जाती है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने इस फैसले को लागू करने के लिए स्थानीय प्रशासन को भी सक्रिय कर दिया है। जिला प्रशासन कार्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे संस्थानों की पहचान करें और यह सुनिश्चित करें कि आदेश का पूरी तरह पालन हो। निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को तुरंत रोका जा सके।

इस फैसले के पीछे सरकार की एक बड़ी सोच यह भी है कि शिक्षा में समान अवसर (Equal Opportunity) सुनिश्चित किया जाए। कोचिंग सेंटरों के बढ़ते प्रभाव के कारण उन छात्रों को अधिक लाभ मिलता था, जो महंगी कोचिंग अफोर्ड कर सकते थे, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र पीछे रह जाते थे। इस असमानता को खत्म करने के लिए सरकार ने यह कड़ा कदम उठाया है।

हालांकि, इस निर्णय को लेकर शिक्षा जगत में मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ विशेषज्ञ इसे छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और समान शिक्षा अवसर के लिए सकारात्मक कदम मान रहे हैं, वहीं कुछ का कहना है कि इससे उन छात्रों को नुकसान हो सकता है, जो प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अतिरिक्त मार्गदर्शन पर निर्भर रहते हैं।

फिलहाल, Nepal सरकार अपने फैसले पर कायम है और इसे सख्ती से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस कदम का शिक्षा व्यवस्था, छात्रों के प्रदर्शन और निजी शिक्षा क्षेत्र पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है।

तीन हफ्तों में हजारों करोड़ का झटका: ईरान टकराव में अमेरिका की सैन्य ताकत पर बड़ा सवाल

United States और Iran के बीच बढ़ता तनाव अब केवल कूटनीतिक बयानबाज़ी या सीमित सैन्य गतिविधियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक ऐसे संघर्ष का रूप ले चुका है जिसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना को भी असहज कर दिया है। महज़ तीन हफ्तों के भीतर अमेरिका को 1.4 से 2.9 अरब डॉलर, यानी लगभग 12,600 करोड़ से 26,000 करोड़ तक का नुकसान हुआ है। यह नुकसान केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी कहानी आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति, रणनीतिक कमजोरियों और तकनीकी चुनौतियों की गवाही देती है।

The Wall Street Journal की रिपोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम को उजागर करते हुए बताया कि यह नुकसान उस समय हुआ है जब जमीनी युद्ध की शुरुआत भी नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि संघर्ष अभी शुरुआती चरण में है, और यदि हालात और बिगड़ते हैं, तो इसका प्रभाव कहीं अधिक व्यापक और गंभीर हो सकता है। यह स्थिति अमेरिका जैसे देश के लिए चिंताजनक है, जो दशकों से अपनी सैन्य श्रेष्ठता और तकनीकी बढ़त पर गर्व करता रहा है।

इस पूरे संघर्ष की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि अमेरिका को अपने ही सहयोगी के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक भ्रम की स्थिति में कुवैत के लड़ाकू विमान द्वारा अमेरिका के F-15E Strike Eagle जेट्स को मार गिराया जाना केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि युद्ध के दौरान संचार और समन्वय में मौजूद खामियों का बड़ा उदाहरण है। यह घटना दिखाती है कि जब कई देशों की सेनाएं एक साथ काम करती हैं, तो एक छोटी सी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। इसके अलावा F-35A Lightning II जैसे अत्याधुनिक और महंगे स्टेल्थ फाइटर को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, जिसे लेकर ईरान ने हमले का दावा किया है। यदि यह दावा सही साबित होता है, तो यह अमेरिका की सबसे उन्नत तकनीक के लिए एक बड़ा झटका माना जाएगा। हवाई युद्ध के साथ-साथ इस संघर्ष ने लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट सिस्टम को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। KC-135 Stratotanker जैसे टैंकर विमान, जो फाइटर जेट्स को हवा में ईंधन देने का काम करते हैं, उनके क्षतिग्रस्त होने से पूरे ऑपरेशन की गति धीमी पड़ जाती है। इराक के हवाई क्षेत्र में हुई टक्कर में छह अमेरिकी सैनिकों की मौत ने यह भी दिखा दिया कि युद्ध केवल मशीनों का नहीं, बल्कि इंसानों की ज़िंदगी का भी सवाल होता है।

इस संघर्ष में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल एक नए स्तर पर देखने को मिला है। MQ-9 Reaper जैसे अत्याधुनिक निगरानी ड्रोन, जो अमेरिका की आंख और कान माने जाते हैं, बड़ी संख्या में नष्ट हो चुके हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका की निगरानी क्षमता और टारगेटिंग सिस्टम पर असर पड़ा है, जिससे उसकी रणनीतिक बढ़त कमजोर हो सकती है। यह संकेत भी मिलता है कि Iran ने एंटी-ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में उल्लेखनीय प्रगति की है।

रक्षा प्रणाली पर पड़े असर ने इस पूरे संघर्ष को और गंभीर बना दिया है। THAAD जैसे हाई-एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का रडार क्षतिग्रस्त होना इस बात का संकेत है कि अमेरिका की रक्षा ढाल भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। कतर और जॉर्डन जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले इस बात को और स्पष्ट करते हैं कि यह संघर्ष केवल सीमित क्षेत्र तक नहीं रह गया, बल्कि इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है।

समुद्री क्षेत्र में भी स्थिति चिंताजनक रही, जब USS Gerald R. Ford जैसे अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर पर आग लगने की घटना सामने आई। यह केवल एक तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि एक रणनीतिक झटका है, क्योंकि ऐसे कैरियर अमेरिका की वैश्विक सैन्य मौजूदगी का प्रतीक होते हैं। इसका अस्थायी रूप से ऑपरेशन से बाहर होना अमेरिका की समुद्री ताकत को प्रभावित करता है।

यदि इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझा जाए, तो यह साफ हो जाता है कि आधुनिक युद्ध अब केवल ताकत और संसाधनों का खेल नहीं रह गया है। यह तकनीक, रणनीति, साइबर क्षमता और रियल-टाइम निर्णय लेने की क्षमता का मिश्रण बन चुका है। Iran ने इस संघर्ष में यह दिखाने की कोशिश की है कि सीमित संसाधनों के बावजूद सही रणनीति और तकनीक के सहारे बड़ी ताकत को चुनौती दी जा सकती है।

इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। यदि यह संघर्ष और बढ़ता है और जमीनी युद्ध शुरू होता है, तो अमेरिका के लिए यह न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर भी बड़ी चुनौती बन सकता है। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें, व्यापार मार्ग और अंतरराष्ट्रीय संबंध भी इससे प्रभावित होंगे।

अंततः, United States के लिए यह एक चेतावनी की तरह है कि भविष्य के युद्धों में केवल हथियारों की संख्या या ताकत ही निर्णायक नहीं होगी, बल्कि तकनीकी श्रेष्ठता, समन्वय और रणनीतिक लचीलापन ही जीत तय करेगा। वहीं Iran के लिए यह एक ऐसा क्षण है, जहां वह अपनी सैन्य क्षमता और रणनीतिक सोच को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर रहा है, जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है।

रेगिस्तान की रात में गूंजे धमाके: सऊदी एयरबेस पर ईरानी हमला, AWACS तबाह, बढ़ा वैश्विक तनाव

पश्चिम एशिया की तपती रेत में उस रात अचानक सन्नाटा टूट गया, जब Iran की ओर से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन की गूंज ने आसमान को चीर दिया। Saudi Arabia के रियाद के पास स्थित प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जो United States की सैन्य मौजूदगी का एक अहम केंद्र माना जाता है, अचानक हमले का निशाना बन गया। कुछ ही मिनटों में वहां का शांत वातावरण आग, धुएं और अफरातफरी में बदल गया।

बताया जाता है कि यह हमला बेहद सुनियोजित और तीव्र था। रात के अंधेरे में जब अधिकतर सैन्य कर्मी अपनी नियमित ड्यूटी पर तैनात थे, तभी एक के बाद एक छह बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 आत्मघाती ड्रोन एयरबेस की ओर बढ़े। एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन हमले की तीव्रता इतनी अधिक थी कि सब कुछ काबू में नहीं रखा जा सका। कुछ ही क्षणों में कई धमाके हुए, जिनकी आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी। इस हमले का सबसे बड़ा झटका उस समय लगा, जब AWACS यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमान को निशाना बनाया गया। यह विमान केवल एक साधारण सैन्य संसाधन नहीं, बल्कि हवा में उड़ता हुआ कमांड सेंटर होता है, जो दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धमाके के बाद यह विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसका ढांचा बीच से टूट गया, जैसे किसी ने उसे दो हिस्सों में चीर दिया हो। यह दृश्य वहां मौजूद सैनिकों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था।

हमले में कम से कम 10 अमेरिकी कर्मियों के घायल होने की खबर सामने आई है। इनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल सैनिकों को तुरंत एयरबेस के मेडिकल यूनिट में ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस घटना ने यह साफ कर दिया कि आधुनिक युद्ध केवल मशीनों का नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगियों का भी बड़ा जोखिम लेकर आता है।

Iran की ओर से यह भी दावा किया गया है कि इस हमले में केवल AWACS ही नहीं, बल्कि कई रिफ्यूलिंग विमान भी क्षतिग्रस्त हुए। साथ ही एक MQ-9 Reaper ड्रोन को मार गिराने और एक F-16 Fighting Falcon लड़ाकू विमान को निशाना बनाने का दावा भी किया गया है। हालांकि United States Central Command की ओर से इन दावों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, जिससे स्थिति और भी पेचीदा हो गई है।

इस पूरे घटनाक्रम के बाद एयरबेस पर सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा केवल बाहर था। अंदर हर कोई आने वाले समय को लेकर चिंतित था। सैन्य अधिकारियों के बीच लगातार बैठकें चल रही हैं, रणनीतियां बनाई जा रही हैं और हर संभावित जवाबी कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। United States के लिए यह केवल एक हमला नहीं, बल्कि उसकी सैन्य प्रतिष्ठा और रणनीतिक बढ़त पर सीधा प्रहार माना जा रहा है।

दूसरी ओर, इस हमले ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। खाड़ी क्षेत्र, जो पहले से ही तनाव का केंद्र रहा है, अब और अधिक अस्थिर नजर आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस तरह के हमले जारी रहते हैं, तो इसका असर केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। तेल की आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग और ऊर्जा सुरक्षा सभी पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है।

रियाद की उस रात के बाद दुनिया की नजरें अब United States की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई हैं। क्या वह जवाबी हमला करेगा? या फिर कूटनीतिक रास्ता अपनाएगा? यह सवाल केवल अमेरिका के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण बन चुका है। क्योंकि इस एक फैसले पर यह निर्भर करेगा कि यह संघर्ष सीमित रहेगा या फिर एक बड़े युद्ध का रूप ले लेगा।

इस पूरी कहानी में एक बात साफ दिखाई देती है—आधुनिक युद्ध अब केवल ताकत का नहीं, बल्कि रणनीति, तकनीक और समय के सही उपयोग का खेल बन चुका है। Iran ने जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया, उसने यह दिखा दिया कि सीमित संसाधनों के बावजूद भी एक मजबूत और सुनियोजित रणनीति के जरिए बड़ी ताकतों को चुनौती दी जा सकती है।

रेगिस्तान की वह रात अब बीत चुकी है, लेकिन उसके निशान अभी भी बाकी हैं—टूटे हुए विमान, घायल सैनिक और एक ऐसा तनाव, जो हर गुजरते दिन के साथ और गहराता जा रहा है। आने वाला समय ही बताएगा कि यह संघर्ष किस दिशा में जाएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि दुनिया एक बार फिर एक बड़े मोड़ पर खड़ी है, जहां हर फैसला इतिहास लिख सकता है।

संपादकीय

जेवर एयरपोर्ट: विकास की नई उड़ान और नीतिगत संकल्प का प्रतीक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन केवल एक आधारभूत ढांचा परियोजना का शुभारंभ नहीं, बल्कि भारत की बदलती आर्थिक दिशा और विकास की नई सोच का सशक्त संकेत है। यह परियोजना उस व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसमें देश के विकास को महानगरों तक सीमित न रखकर क्षेत्रीय संतुलन के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक गतिविधियों और यातायात के दबाव को देखते हुए इस एयरपोर्ट की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। एयरपोर्ट किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए केवल परिवहन का साधन नहीं होते, बल्कि वे विकास के केंद्र बन जाते हैं। जहां एयरपोर्ट बनता है, वहां रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, निवेश को बढ़ावा मिलता है और स्थानीय उद्योगों को वैश्विक बाजार से जुड़ने का अवसर मिलता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ भी ऐसी ही संभावनाएं जुड़ी हुई हैं। यह न केवल दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बढ़ते दबाव को कम करेगा, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों को वैश्विक संपर्क से जोड़ेगा। इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। यह उपलब्धि केवल एक सांख्यिकीय तथ्य नहीं, बल्कि राज्य के बदलते विकास मॉडल का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश, जो लंबे समय तक पिछड़ेपन और सीमित औद्योगिक विकास के लिए जाना जाता रहा, अब बुनियादी ढांचे और निवेश के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह बदलाव न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर भी पैदा करेगा। पिछले डेढ़ दशक में भारत में हवाई अड्डों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जहां पहले देश में लगभग 75 एयरपोर्ट थे, वहीं अब यह संख्या 160 से अधिक हो चुकी है। यह वृद्धि केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि हवाई यात्रा अब आम नागरिकों की पहुंच में आ रही है। पहले जहां हवाई यात्रा को केवल संपन्न वर्ग के लिए माना जाता था, वहीं आज मध्यम वर्ग और सामान्य लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं। यह परिवर्तन देश की आर्थिक प्रगति और बढ़ते जीवन स्तर का स्पष्ट संकेत है। हालांकि, इस प्रगति के बावजूद उड्डयन क्षेत्र में कई चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। विशेष रूप से विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सुविधाओं की कमी एक बड़ी समस्या है। आज भी भारत के लगभग 85 प्रतिशत विमान सर्विसिंग के लिए विदेश भेजे जाते हैं, जिससे समय और धन दोनों की हानि होती है। ऐसे में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ एमआरओ सुविधा का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि इस प्रकार की सुविधाएं देश के अन्य हवाई अड्डों पर भी विकसित की जाएं, तो भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है और वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को मजबूत कर सकता है। इस परियोजना की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता इसकी लंबी प्रतीक्षा है। वर्ष 2001 में इस एयरपोर्ट का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इसे साकार होने में लगभग 25 वर्ष लग गए। यह देरी हमारे प्रशासनिक ढांचे की जटिलताओं और नीतिगत असंगतियों को उजागर करती है। भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृतियां, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और बदलती सरकारों के कारण इस परियोजना में बार-बार बाधाएं आईं। इस प्रकार की देरी का सीधा असर देश के संसाधनों और विकास की गति पर पड़ता है। यह आवश्यक है कि भविष्य में इस तरह की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए स्पष्ट और समयबद्ध नीति बनाई जाए। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही, सभी राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि बुनियादी ढांचे का विकास किसी एक दल की उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे देश की आवश्यकता है। इसलिए इन परियोजनाओं को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि एक आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन सकता है। यदि इसके आसपास औद्योगिक क्षेत्र, लॉजिस्टिक्स हब, सड़क और रेल नेटवर्क का समुचित विकास किया जाए, तो यह क्षेत्र एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में उभर सकता है। इससे न केवल स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि क्षेत्रीय असमानताओं को भी कम करने में मदद मिलेगी।

अंततः, जेवर एयरपोर्ट की यह पहल हमें यह सिखाती है कि जब दूरदृष्टि, मजबूत नेतृत्व और प्रभावी क्रियान्वयन एक साथ आते हैं, तो बड़े से बड़े सपने भी साकार हो सकते हैं। यह परियोजना भारत के विकास की नई उड़ान का प्रतीक है, जो देश को वैश्विक मंच पर और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

कई सभ्यताओं को नष्ट किया जलवायु परिवर्तन ने

> सूखा ही नहीं बहुत ज्यादा पानी भी उतना ही नुकसानदायक हो सकता है। शिजियाहे की कहानी सिर्फ यही कहती है कि समाज को अव्यवस्थित करने के लिए चरम जलवायु को रिकॉर्ड तोड़ने की जरूरत नहीं, उसे बस लंबे समय तक टिकने की जरूरत है।

मानव इतिहास में जलवायु का हमेशा से ही अहम रोल रहा है। अच्छी जलवायु में अनेक सभ्यताओं का उत्थान हुआ और जलवायु बिगड़ने पर कई सभ्यताओं का पतन हुआ। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मौजूद हैं। जब सही समय पर बारिश होती है, तो फसलें उगती हैं और शहर फलते-फूलते हैं। जब ऐसा नहीं होता, तो लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। लगभग 4,200 साल पहले, धरती पर एक बड़ा जलवायु परिवर्तन हुआ था। मध्य पूर्व से लेकर एशिया तक की सभ्यताओं ने मुश्किलें झेलीं। मध्य चीन में, शिजियाहे संस्कृति के नाम से जाना जाने वाला एक बड़ा और संगठित समाज खत्म होने लगा। सालों तक शोधकर्ता इस बात पर बहस करते रहे कि शिजियाहे के पुराने शहर को क्यों छोड़ दिया गया था। पहले उनका शक सूखे पर था।

वैज्ञानिकों की एक टीम ने अब शिजियाहे के पतन का कारण यांग्त्ज़ी वैली में बार-बार, लंबे समय तक होने वाली बारिश को बताया है। उनके नतीजों से पता चलता है कि इस इलाक़े में जबरदस्त बाढ़ आई थी। यह समझने के लिए कि वास्तव में क्या हुआ, शोधकर्ता जमीन के नीचे गए। यांग्त्ज़ी वैली के बीच में हेशांग गुफा के अंदर, उन्होंने स्टैलेग्माइट (कैल्शियम कार्बोनेट के भंडार) की स्टडी की जो गुफा के फ़र्श से धीरे-धीरे बढ़ रहा था। स्टैलेग्माइट तब बनते हैं जब छत से बारिश का पानी टपकता है और कैल्शियम कार्बोनेट की छोटी-छोटी परतें पीछे छोड़ जाता है।

साल दर साल, ये परतें इतिहास की किताब के पन्नों की तरह जमा होती जाती हैं। उन परतों की रासायनिक बनावट को मापकर शोधकर्ताओं ने एक ऐसी चीज बनाई जिसे उन्होंने 'रेनफाल इयरबुक' कहा। उन्होंने 1,000 साल की अवधि में हर साल कितनी बारिश हुई, यह पता लगाने के लिए 925 सैंपल माप लिए। इसके नतीजे साफ थे। घाटी में तीन सूखे दौर आए। हर दौर 40 से 150 साल तक चला, जब बारिश 700 मिलीमीटर प्रति साल (लगभग 28 इंच) से कम हो गई। इसने दो बहुत ज़्यादा बारिश वाले दौर भी झेले। एक 80 साल और दूसरा 140 साल, जब बारिश प्रति वर्ष 1,000 मिलीमीटर से ज्यादा हो गई।

जब शोधकर्ताओं ने बारिश के रिकॉर्ड की तुलना पुरातात्विक सबूतों से की, तो पैटर्न साफ हो गया। बारिश वाले दौर में गंभीर बाढ़, फैलती आर्द्रभूमि और आबादी में तेज गिरावट के संकेत मिले। लगभग 3,950 साल पहले इस इलाके में रिकॉर्ड में सबसे लंबे समय तक भारी बारिश हुई। झीलें फैल गईं। निचली जमीन गीली हो गई और खेती की जमीन कम हो गई। उसी समय, शिजियाहे कल्चर से जुड़े पुरातात्विक अवशेषों की संख्या कम होने लगी। यह गिरावट थोड़ी देर के लिए नहीं थी। यह सदियों तक चली। सबूत बताते हैं कि जो लोग बच गए, उन्होंने घाटी में अपना शहरी ठिकाना छोड़ दिया और ऊंची जगहों पर चले गए।

यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड के अर्थ साइंसेज़ डिपार्टमेंट और चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियोसाइंसेज़ (वुहान) की टीमों ने इस रिसर्च का नेतृत्व किया है। उन्होंने अपने अध्ययन में एक गुफा के अंदर के क्लाइमेट रिकॉर्ड को जमीन के ऊपर एक संगठित समाज की नियति से जोड़ा है। अध्ययन में एक खास बात सामने आई। शोधकर्ताओं ने पाया कि शिजियाहे सभ्यता के खत्म होने से जुड़े ज्यादा बारिश के समय के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश आज के समय में रिकॉर्ड की गई कुछ बहुत ज़्यादा बारिश की घटनाओं से कम थी। यह बात मायने रखती है। पुराने समाजों में बांध, तटबंध, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम या बड़े पैमाने पर बाढ़ नियंत्रण की प्लानिंग नहीं थी। वे स्थिर मौसमी पैटर्न पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। जब वे पैटर्न टूट गए, तो विकल्प कम हो गए।

शिजियाहे कल्चर ने बड़ी बस्तियां बनाई थीं और एडवांस्ड क्राफ्ट और ट्रेड नेटवर्क डेवलप किए थे। लेकिन ये लोग बढ़ती झीलों को भर नहीं सके या उन खेतों को वापस नहीं पा सके जो साल दर साल पानी में डूबे रहते थे। समय के साथ, दूर जाना ही शायद एकमात्र सही विकल्प रहा होगा। यह रिसर्च गर्म होती दुनिया के लिए सबक है। यह दिखाती है कि इंसानी सिस्टम बारिश में लंबे समय तक होने वाले बदलावों के प्रति कितने संवेदनशील हो सकते हैं। बहुत कम पानी खतरनाक है। बहुत ज्यादा पानी भी उतना ही नुकसानदायक हो सकता है। शिजियाहे की कहानी सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है। समाज को अव्यवस्थित करने के लिए चरम जलवायु को रिकॉर्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है। उसे बस लंबे समय तक टिकने की जरूरत है। चार हजार साल पहले, नियमित बारिश निरंतर बारिश में बदल गई। खेत डूब गए। शहर खाली हो गए। एक कल्चर जो कभी यांग्त्ज़ी घाटी के बीच में फली-फूली, वह ऊंची जमीन पर बिखर गई। हेशांग की गुफा हर बूंद का हिसाब रखती थी। अब इसने सारी कहानी कह दी है। इस तरह की कहानियां दुनिया में दूसरी जगहों पर भी दोहराई गई हैं।

अतीत में भारत पर भी जलवायु परिवर्तन का असर पड़ा। वर्ष 1900 ईसा पूर्व और 1300 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी की हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। यह परिवर्तन अचानक नहीं बल्कि पर्यावरणीय गिरावट, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक पतन के कारण धीरे-धीरे हुआ। नदियों के मार्ग में परिवर्तन, भीषण सूखा, बाढ़ और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन इसके प्रमुख कारण थे, जिससे पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न हुआ। मानसून के कमजोर होने और शुष्कता बढ़ने से पानी की गंभीर कमी हो गई और कृषि उत्पादन में गिरावट आई, जिसके कारण आबादी को पूर्व और दक्षिण की ओर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ईंटें पकाने के लिए वनों की कटाई और संसाधनों के अत्यधिक दोहन के साथ-साथ लवणता में वृद्धि ने संभवतः भूमि की उर्वरता को नष्ट कर दिया। सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन और सरस्वती नदी के सूखने से कुछ क्षेत्रों में भीषण बाढ़ आई और अन्य क्षेत्रों में सूखा पड़ा। मेसोपोटामिया और संभवतः अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार में गिरावट ने शहरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। आज दुनिया तेजी से गर्म हो रही है। इसके परिणाम भी हम देख रहे हैं। यदि हमने जलवायु परिवर्तन के कारणों को समय रहते दूर नहीं किया तो हमें भविष्य में बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है।

प्रेरणा

ब्रह्मांड का रहस्य और सनातन की कहानी: एक साधक की अद्भुत यात्रा

प्रयागराज के संगम किनारे सर्दियों की हल्की धूप फैली हुई थी। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम मानो किसी गहरे रहस्य को अपने भीतर समेटे बह रहा था। इसी किनारे पर बैठा था एक युवक—अद्वैत। उसके मन में वर्षों से एक प्रश्न घूम रहा था—"यह सृष्टि आखिर बनी कैसे? और हिन्दू संस्कृति इतनी विस्तृत और रहस्यमयी क्यों है?"

अद्वैत ने बहुत किताबें पढ़ीं, विज्ञान को समझा, इतिहास को जाना, लेकिन उसके प्रश्नों का पूर्ण उत्तर कहीं नहीं मिला। एक दिन, संगम किनारे उसे एक संत मिले—शांत, स्थिर और तेजस्वी। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी, जैसे वे सब कुछ जानते हों, लेकिन फिर भी कुछ भी जताना न चाहते हों।

अद्वैत ने झुककर प्रणाम किया और पूछा, "गुरुदेव, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सृष्टि का आरंभ कब और कैसे हुआ?"

संत ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और बोले, "तुम जिस उत्तर की तलाश में हो, वह केवल शब्दों में नहीं मिलेगा। उसे समझने के लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी—ज्ञान की, अनुभव की और भीतर की।"

इतना कहकर संत ने उसे एक पुरानी पुस्तक दी, जिसमें हिन्दू संस्कृति और सृष्टि के विकास का वर्णन था। अद्वैत ने पुस्तक खोली, और जैसे ही पढ़ना शुरू किया, वह मानो एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया।

उसे दिखा—एक अनंत शून्य, जहां कुछ भी नहीं था, न समय, न दिशा, न जीवन। फिर उस शून्य से एक कंपन उत्पन्न हुआ—एक ऊर्जा, जिसे सनातन में 'ब्रह्म' कहा गया है। उसी से सृष्टि की शुरुआत हुई। ब्रह्मा ने सृजन किया, विष्णु ने उसका पालन किया और शिव ने समय आने पर उसका संहार किया।

अद्वैत ने महसूस किया कि यह केवल देवताओं की कथा नहीं, बल्कि सृष्टि के नियमों का प्रतीक है—निर्माण, संरक्षण और परिवर्तन।

आगे बढ़ते हुए उसने चार युगों की कथा पढ़ी—सत्ययुग, जहां सत्य और धर्म अपने चरम पर थे; त्रेतायुग, जहां मर्यादा और आदर्शों की स्थापना हुई; द्वापरयुग, जहां धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष बढ़ा; और अंततः कलियुग, जिसमें हम आज जी रहे हैं।

अचानक दृश्य बदल गया। अद्वैत ने खुद को वर्तमान समय में देखा—भागती-दौड़ती जिंदगी, स्वार्थ से भरे रिश्ते और भ्रम में उलझा हुआ समाज। उसे समझ में आया कि क्यों कहा जाता है कि कलियुग में सत्य कम और असत्य अधिक दिखाई देता है।

तभी संत की आवाज गूंजी—"लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। हर युग में प्रकाश और अंधकार दोनों होते हैं। फर्क केवल इतना है कि तुम किसे देखना चुनते हो।"

अद्वैत ने आगे पढ़ा—हिन्दू संस्कृति का विकास कैसे हुआ। वैदिक काल में यज्ञ और मंत्रों का महत्व था, जहां प्रकृति के तत्वों को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती थी। फिर महाकाव्य काल आया, जिसमें राम और कृष्ण जैसे आदर्शों ने मानव जीवन को दिशा दी। भक्ति काल में ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण को सर्वोच्च स्थान मिला।

पुस्तक में देवी-देवताओं के बारे में विस्तार से बताया गया था—शिव, जो विनाश के नहीं, बल्कि परिवर्तन के देवता हैं; विष्णु, जो संतुलन बनाए रखते हैं; और देवी, जो शक्ति और सृजन का रूप हैं। हर देवता का एक वाहन है, जो यह दर्शाता है कि सृष्टि का हर जीव और तत्व महत्वपूर्ण है।

अद्वैत को सबसे रोचक लगा पूजा-पाठ के नियमों का वर्णन। उसे पता चला कि गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई जाती है, तुलसी नहीं; अलग-अलग देवताओं के लिए अलग दीपक और बत्ती का उपयोग होता है। यह सब केवल परंपरा नहीं, बल्कि ऊर्जा और प्रकृति के संतुलन से जुड़ा हुआ विज्ञान है।

फिर उसने महिलाओं के सुहाग चिन्हों के बारे में पढ़ा—सिंदूर, जो केवल श्रृंगार नहीं, बल्कि जीवन ऊर्जा का प्रतीक है; करवाचौथ, जो प्रेम और समर्पण का उत्सव है; तीज-त्योहार, जो प्रकृति और जीवन के चक्र को दर्शाते हैं।

पुस्तक में आगे बताया गया था कि हिन्दू संस्कृति केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है। इसमें पशु-पक्षियों को भी उतना ही महत्व दिया गया है। हर देवता का वाहन—नंदी, गरुड़, उल्लू, शेर—यह दर्शाता है कि सृष्टि में हर जीव का अपना स्थान है।

अद्वैत की यात्रा यहीं नहीं रुकी। उसने 12 राशियों और उनके प्रतीकों के बारे में जाना, सप्तऋषियों की कथा पढ़ी, पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझा और यह भी जाना कि जीवन केवल एक जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा अनंत यात्रा पर है।

उसे यह भी ज्ञात हुआ कि पितृदोष, 12 माह, सप्तपुरी, महाकुंभ जैसे आयोजन केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि समय, प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य स्थापित करने के उपाय हैं।

अचानक अद्वैत की आंखें खुल गईं। वह फिर से संगम किनारे बैठा था। संत उसके सामने मुस्कुरा रहे थे।

"क्या तुम्हें तुम्हारे उत्तर मिल गए?" संत ने पूछा।

अद्वैत ने शांत स्वर में कहा, "उत्तर तो नहीं, लेकिन अब मुझे प्रश्नों से डर नहीं लगता। अब मैं समझ गया हूं कि सृष्टि एक रहस्य है, और हिन्दू संस्कृति उस रहस्य को समझने का एक मार्ग है।"

संत ने कहा, "यही सबसे बड़ा ज्ञान है। सृष्टि को पूरी तरह समझ पाना शायद संभव नहीं, लेकिन उसे महसूस करना, उसके साथ जीना—यही सनातन का सार है।"

अद्वैत ने गंगा की ओर देखा। जल बह रहा था, लेकिन हर लहर में एक स्थिरता थी। उसे लगा जैसे सृष्टि भी ऐसी ही है—लगातार बदलती हुई, फिर भी हमेशा एक जैसी।

उस दिन के बाद अद्वैत बदल गया। अब वह उत्तरों की खोज में नहीं भटकता था, बल्कि हर अनुभव में, हर परंपरा में और हर जीव में सृष्टि की झलक देखने लगा था।

और शायद यही हिन्दू संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है—यह हमें केवल धर्म नहीं सिखाती, बल्कि जीवन को समझने की कला देती है। यह बताती है कि हम केवल इस सृष्टि का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि स्वयं सृष्टि का ही एक रूप हैं।

इस अनंत यात्रा में, जहां हर प्रश्न एक नया द्वार खोलता है, वहीं हर उत्तर हमें अपने और करीब ले जाता है। यही सनातन है—न कभी शुरू होने वाला, न कभी समाप्त होने वाला, बस निरंतर प्रवाहित होता हुआ।

दूरगामी असर वाले विधानसभा चुनाव, एसआईआर से लेकर परिसीमन तक तक व्यापक फैसले

अगले डेढ़ माह में चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में नई सरकार बननी है। नजरें इस पर टिकी हैं कि इन राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टी क्या वापस जनादेश पाती है या फिर विपक्ष में बैठे दल काबिज होते हैं? जाहिर तौर पर वापसी का बड़ा कारण तो जनहित में लिए गए फैसले ही होते हैं, पर महत्वपूर्ण कारक विभिन्न दलों के नेतृत्व की विश्वसनीयता भी है

एक पहलू नैरेटिव का भी होता है। जनता यह आकलन करती है कि केवल उनका ही नहीं, उनके बच्चों का भी भविष्य संबंधित दल कितना सुरक्षित रख पाएंगे? विधानसभा चुनावों में हालांकि यह सीमित होता है, पर कई बार तो यह पैमाना परिवार और बच्चों से आगे बढ़कर देश तक पहुंचता है। चुनावी राज्यों में ये पहलू प्रभावी रहने वाले हैं। असम को लेकर बहुत असमंजस नहीं है और इसका बड़ा कारण यह है कि विपक्षी कांग्रेस के नेता भी अपनी तैयारी से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। नेतृत्व, प्रदर्शन और नैरेटिव के मोर्चे पर फिलहाल सत्ताधारी भाजपा काफी आगे खड़ी है। राज्य में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और भाजपा इसके विरुद्ध चैंपियन बनकर खड़ी है। पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेश है और वहां तमिलनाडु की राजनीति का असर होता है।

लिहाजा तमिलनाडु, केरल और सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में देश की रुचि है। बंगाल की जनसांख्यिकी के साथ 15 साल से सत्ता में बनीं ममता बनर्जी की जो राजनीति है, उसमें कोई भी यह भविष्यवाणी करने से बच रहा है कि वह चौथी बार सत्ता में नहीं आ सकतीं, पर एक फार्मूला इन तीनों राज्यों में बहुत प्रखर है और वह है एंटी इनकंबेंसी। बंगाल की लगभग एक चौथाई सीटें ऐसी हैं, जहां 30 प्रतिशत से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं और वे नैरेटिव के आधार पर भाजपा के खिलाफ हैं।

ममता की चुनावी शक्ति का यह बड़ा आधार है, लेकिन उन्हें पिछली बार इसका अहसास हो गया था कि जमीन भुरभुरी हो रही है। विकास की तड़प और बदलाव की छटपटाहट भी एक बड़े वर्ग में है। प्रबुद्ध वर्ग के अंदर तृणमूल सरकार की कई नीतियों को लेकर बेचैनी है। संदेशखाली से लेकर आरजी कर मेडिकल कालेज में महिलाओं के साथ हुई निर्ममता ने महिला सुरक्षा और संवेदनशीलता को झकझोर दिया है। विपक्षी दल इसे फिर से याद दिला रहे हैं। ममता सरकार इससे अनभिज्ञ नहीं होगी, लेकिन पता नहीं कि वे भद्रलोक की आशंकाओं को निर्मूल करने के लिए क्या कर रही हैं?

माना जा रहा है कि इस बार का बंगाल चुनाव मुख्यतः कोलकाता प्रेसीडेंसी या ग्रेटर कोलकाता में ही लड़ा जाएगा, जहां पिछली बार भाजपा फिसड्डी रह गई थी। हावड़ा, हुगली, दक्षिण और उत्तर 24 परगना तथा नादिया में लगभग सवा सौ सीटें हैं। पिछली बार भाजपा के बड़े नेताओं ने इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार ही नहीं किया था। कोविड के कारण आखिरी के तीन चरणों में प्रधानमंत्री मोदी ने निर्णय लिया था कि चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा। इसे विपक्षी दल भी खारिज नहीं करते कि आखिरी दिनों में होने वाले प्रचार में मोदी कुछ बदलाव तो ला ही देते हैं। बंगाल में आठ चरणों के मुकाबले होने वाले दो चरणों के चुनाव भी अहम हो सकते हैं। इस बार चुनाव एक सप्ताह के अंदर ही खत्म होगा। इससे उपद्रवियों की गतिविधियां भी बहुत सीमित होने की उम्मीद है। इस सबके बावजूद फिलहाल ममता को खारिज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अपने लंबे राजनीतिक संघर्ष में उन्होंने यह साबित किया है कि वह एक फाइटर हैं और एक बड़ी हद तक बंगाल के मूड का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी जीत विपक्षी दलों में उन्हें सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित कर देगी, पर यदि वह हारती हैं तो भाजपा के लिए यह बिहार, दिल्ली और महाराष्ट्र से भी बड़ी जीत होगी। उसे विस्तार के लिए एक नई जमीन मिलेगी और इसका असर 2029 तक जाएगा, पर एक बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि बंगाल की राजनीतिक संस्कृति बदलना बहुत आसान नहीं।

केरल में पिछली बार भी एंटी इनकंबेंसी थी, पर अंदरूनी लड़ाई में कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ माकपा के अगुआई वाले एलडीएफ से दोबारा हार गया था। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखने वाली माकपा इस बार देश की राजनीति में गुम हो सकती है। वाम विचारधारा की इस सिकुड़न को सिर्फ एक राज्य की विधानसभा से जोड़कर देखना सही नहीं होगा। जानकार कांग्रेस के गिरते ग्राफ को भी इसी विचारधारा से जोड़कर देखते हैं। बंगाल में वाम दल ममता के हाथों हारे, त्रिपुरा में भाजपा के हाथों और अब केरल में कांग्रेस के हाथों साफ होने की कगार पर हैं। केरल में वाम मोर्चे के लिए और बड़ी परेशानी यह है कि वहां कमल खिलने लगा है।

त्रिवेंद्रम नगर निगम में वाम दलों के पांच दशक के शासन को भाजपा ने छीना है। विधानसभा में पैर जमे तो वाम दलों का हिंदू जनाधार डोल सकता है। ऐसे में केरल कांग्रेस के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक आधा दर्जन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और कांग्रेस को अच्छी खबर कहीं से नहीं मिली। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार ने कांग्रेस को हाशिए पर रखा। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार में जरूर प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन इकबाल नहीं मिला। जबकि हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और दिल्ली में भाजपा और राजग ने बाजी मार ली।

तमिलनाडु में एमके स्टालिन को सत्ता से बाहर करने की कोशिश कर रहे विपक्षी दलों का भरोसा इस पर टिका है कि एंटी इनकंबेंसी काम कर जाएगी। यह एक फैक्टर तो है, पर चुनाव के लिए जिस नेतृत्व की जरूरत होती है, वह फिलहाल उस अन्नाद्रमुक में नहीं दिख रहा, जो राजग का नेतृत्व करेगा। सिने स्टारों की इस राज्य में धमक होती है और इस बार विजय के साथ राज्य के युवा दिख रहे हैं, पर यदि वे ही एंटी इनकंबेंसी वोट ले गए तो स्टालिन की राह आसान हो जाएगी। भाजपा के लिए यह शुभ नहीं होगा, क्योंकि केरल की तरह पार्टी यहां भी भविष्य का आधार रखना चाह रही है।

2029 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में परिसीमन भी हो जाएगा, सीटों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो जाएगी और महिला आरक्षण भी लागू हो जाएगा, इसलिए एसआईआर के साथ होने वाले इन चुनावों का असर दूर तक दिखेगा।

अभियान

कूर्म कृपा की कथा: जब एक छोटा सा कछुआ बदल गया पूरे घर का भाग्य

गोरखपुर के पास एक छोटे से कस्बे में रहने वाले रामनारायण जी का जीवन किसी आम इंसान की तरह ही था—सीमित आय, जिम्मेदारियों का बोझ और मन में हमेशा एक चिंता कि आखिर कब उनके घर में सुख-समृद्धि का स्थायी वास होगा। उनकी पत्नी सीता देवी भगवान में गहरी आस्था रखती थीं। रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा करतीं, तुलसी को जल चढ़ातीं और पूरे घर में धूप-दीप से सकारात्मक वातावरण बनाने की कोशिश करतीं। लेकिन फिर भी जैसे घर में कुछ अधूरा था, जैसे कोई ऊर्जा रुक-रुक कर बह रही हो।

एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। लोग उन्हें "स्वामी कूर्मानंद" के नाम से जानते थे। कहते थे कि वे वास्तु और सनातन रहस्यों के ज्ञाता हैं। सीता देवी ने रामनारायण जी से कहा, "चलो, उनके दर्शन कर आते हैं। शायद हमारे जीवन की उलझन का कोई हल मिल जाए।"

दोनों संत के पास पहुंचे। संत ने उन्हें देखते ही मुस्कुराकर कहा, "तुम्हारे घर में आस्था है, भक्ति है, लेकिन ऊर्जा का प्रवाह बाधित है।" रामनारायण जी चौंक गए—बिना कुछ बताए ही संत ने उनके मन की बात जान ली थी।

सीता देवी ने विनम्रता से पूछा, "गुरुदेव, इसका उपाय क्या है?"

संत ने धीरे से कहा, "तुम्हें अपने घर में कूर्म यानी कछुए को स्थान देना होगा। लेकिन ध्यान रहे—यह केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के कूर्म अवतार का प्रतीक है। इसे सही विधि और भावना से स्थापित करना होगा।"

रामनारायण जी ने आश्चर्य से पूछा, "क्या एक कछुआ हमारे जीवन को बदल सकता है?"

संत मुस्कुराए, "जब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर समुद्र मंथन में पूरी सृष्टि का संतुलन संभाला, तो क्या वह केवल एक कछुआ थे? नहीं वह शक्ति, स्थिरता और धैर्य का प्रतीक थे। अगर उसी ऊर्जा को सही रूप में घर में लाया जाए, तो वह चमत्कार कर सकती है।"

अगले दिन रामनारायण जी बाजार गए। वहां उन्हें कई तरह के कछुए दिखे—पीतल, चांदी, क्रिस्टल और मिट्टी के। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा लें। तभी उन्हें संत की बात याद आई—"धातु का चुनाव तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए।" उन्होंने अपनी स्थिति को देखते हुए एक सुंदर पीतल का कछुआ खरीदा। उनके मन में इच्छा थी कि उनके बेटे को अच्छा भविष्य मिले और घर में आर्थिक स्थिरता आए।

घर आकर उन्होंने संत के बताए अनुसार कछुए को एक कांच के पात्र में रखा और उसमें स्वच्छ जल भरा। फिर उसे घर की उत्तर दिशा में स्थापित किया। सीता देवी ने विधिपूर्वक पूजा की और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कछुए को प्रणाम किया।

धीरे-धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। पहले जहां छोटी-छोटी बातों पर तनाव होता था, वहां अब शांति का अनुभव होने लगा। रामनारायण जी के काम में भी सुधार आने लगा। उनका छोटा व्यापार, जो पहले घाटे में चल रहा था, अब धीरे-धीरे लाभ देने लगा। एक दिन उनका बेटा, जो लंबे समय से नौकरी की तलाश में था, अचानक एक अच्छी कंपनी में चयनित हो गया। उस दिन सीता देवी की आंखों में आंसू थे—खुशी के आंसू।

कुछ महीनों बाद, गांव के लोग भी यह बदलाव देखने लगे। सब पूछने लगे, "आखिर ऐसा क्या किया कि आपके घर में इतनी खुशहाली आ गई?"

सीता देवी मुस्कुराकर कहतीं, "यह सब भगवान की कृपा है और कूर्म का आशीर्वाद।"

लेकिन एक दिन एक पड़ोसी ने उनकी देखा-देखी दो कछुए खरीद लिए और उन्हें अपने बेडरूम में रख दिया। कुछ ही दिनों में उनके घर में कलह शुरू हो गई। वे परेशान होकर रामनारायण जी के पास आए।

रामनारायण जी ने उन्हें संत के पास जाने की सलाह दी। संत ने उन्हें समझाया, "कछुआ केवल सजावट की वस्तु नहीं है। इसे सही दिशा, सही संख्या और सही स्थान पर रखना आवश्यक है। दो कछुए रखने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता है और बेडरूम में रखने से मानसिक अशांति बढ़ती है।"

पड़ोसी ने अपनी गलती सुधारी और कुछ समय बाद उनके घर में भी शांति लौट आई।

रामनारायण जी अब रोज सुबह कछुए के पास दीप जलाते, जल बदलते और भगवान विष्णु का ध्यान करते। उनके लिए वह कछुआ केवल धातु का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक जीवंत प्रतीक था—धैर्य, संतुलन और ईश्वर की कृपा का।

समय के साथ उनका घर एक ऐसा स्थान बन गया, जहां आने वाला हर व्यक्ति शांति और सकारात्मकता का अनुभव करता। लोगों को लगता मानो वहां कोई अदृश्य शक्ति हर समय मौजूद है।

एक दिन रामनारायण जी ने संत से पूछा, "गुरुदेव, क्या सच में यह सब कछुए की वजह से हुआ?"

संत ने हंसते हुए कहा, "कछुआ केवल माध्यम है। असली परिवर्तन तुम्हारी आस्था, श्रद्धा और सही विधि के पालन से आया है। जब तुमने उसे भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर स्थापित किया, तब तुम्हारे घर में दिव्य ऊर्जा का प्रवेश हुआ।"

उन्होंने आगे कहा, "याद रखो, किसी भी वस्तु में शक्ति तभी आती है जब उसे सही भावना और नियमों के साथ अपनाया जाए। वरना वही वस्तु नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती है।"

रामनारायण जी ने सिर झुका लिया। अब उन्हें समझ में आ गया था कि जीवन में केवल उपाय करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे सही तरीके और श्रद्धा के साथ करना भी उतना ही जरूरी है।

उस दिन के बाद से उनका विश्वास और भी गहरा हो गया। उनके लिए कछुआ अब केवल एक वास्तु उपाय नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के कूर्म अवतार का साक्षात प्रतीक बन चुका था।

और शायद यही सनातन का सार है—जहां हर छोटी से छोटी वस्तु भी, यदि सही भावना और नियमों के साथ अपनाई जाए, तो वह जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। जहां भक्ति, विज्ञान और प्रकृति एक साथ मिलकर मनुष्य को न केवल सुख-समृद्धि देते हैं, बल्कि आत्मिक शांति का मार्ग भी दिखाते हैं।

इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि घर में कछुआ रखना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक सिद्धांत है। यदि इसे सही धातु, सही दिशा और सही विधि के साथ स्थापित किया जाए, तो यह न केवल धन और समृद्धि लाता है, बल्कि जीवन में स्थिरता, शांति और संतुलन भी प्रदान करता है।

और अंत में, यही संदेश रह जाता है—जब भक्ति और ज्ञान का संगम होता है, तब साधारण से साधारण उपाय भी असाधारण परिणाम दे सकते हैं।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से अहमदाबाद शहर को 1,099 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की भेंट : विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया

▸▸ नागरिकों के जीवन को अधिक सरल एवं सुविधाजनक बनाने को राज्य सरकार ने प्राथमिकता दी है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ अहमदाबाद वैश्विक पहचान की ओर बढ़ रहा है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ आवास, ब्रिज, पार्क-बगीचे, तालाब, ऑडिटोरियम और शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से नागरिकों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी

▸▸ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों को टेक्नोलॉजी से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध : महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मनीषाबेन वकील

अहमदाबाद के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध : राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से रविवार को अहमदाबाद शहर के सर्वांगीण विकास को नई गति देने के लिए 1,099 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर शहर के नागरिकों को आवास, ब्रिज, पार्क-बगीचे, तालाब, ऑडिटोरियम तथा अन्य आधुनिक शहरी सुविधाओं की महत्वपूर्ण भेंट मिली।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने शहरों के विकास में नागरिकों के जीवन को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2005 में 'शहरी विकास वर्ष' मनाकर जो विकास यात्रा शुरू की थी, वह आज और तेज गति से आगे बढ़ रही है। उनके मार्गदर्शन अंतर्गत गुजरात में 2025 को भी 'शहरी विकास वर्ष' के रूप में मनाया गया। प्रधानमंत्री के प्रयासों से अहमदाबाद को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का गौरव प्राप्त हुआ है। आज अहमदाबाद अपनी वैश्विक पहचान बनाए रखते हुए आधुनिक विकास की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। नागरिकों की सुख सुविधा बढ़े तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं मजबूत बने इसके लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयत्नशील है।

श्री पटेल ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में अहमदाबाद शहर में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। जिनमें 13,000 से अधिक सड़क कार्य, स्टॉर्म वॉटर और सीवरेज कार्य के लिए 6,152 कार्य तथा स्वच्छ पेयजल के लिए जल वितरण प्रणाली को मजबूत करने की कई योजनाएं लागू की गई हैं।

उन्होंने कहा कि अहमदाबाद को ग्रीन सिटी बनाने के प्रयासों में भी उल्लेखनीय सफलता मिली है। इस दिशा में गांधीनगर के सांसद तथा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की प्रेरणा से 110 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से लगभग 450 विकास कार्य किए गए हैं। उन्होंने जोड़ा कि शहर में बेहतर तथा सुविधापूर्ण सार्वजनिक परिवहन के लिए 2,561 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 21 शहरी परिवहन परियोजनाएं लागू की गई हैं। अहमदाबाद में बीआरटीएस और मेट्रो नेटवर्क को आधुनिक मॉडल सार्वजनिक परिवहन के रूप में विकसित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'हर व्यक्ति के सिर पर पक्की छत' के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत अहमदाबाद में उल्लेखनीय कामकाज हुआ है। शहर में 4,501 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से हजारों लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में भी अहमदाबाद ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 'सबसे स्वच्छ शहर' का पुरस्कार प्राप्त किया है।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अहमदाबाद शहर में कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का आयोजन होने वाला है, इसलिए शहर को वैश्विक मानकों के अनुसार विकसित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा साबरमती रिवरफ्रंट को गिफ्ट सिटी तक विस्तारित करने की योजना है। गांधी आश्रम पुनर्विकास परियोजना देश-विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है, जिससे पूरे क्षेत्र के होलिस्टिक विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इसके साथ ही राज्य सरकार ने 'सुपोषित गुजरात' के संकल्प को साकार करने के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं को डिजिटल बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 'पोषण ट्रैक' एप्लिकेशन द्वारा लाभार्थियों की जानकारी रियल टाइम में अपडेट होगी, सेवाओं की निगरानी अधिक मजबूत बनेगी और गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य का समय पर अनुसरण संभव हो सकेगा। इसके लिए आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों को स्मार्टफोन भी वितरित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि हमारे शहर, महानगर और गांव स्वच्छ, हरित और क्लाइमेट फ्रेंडली बनें, इसके लिए सभी को संकल्पबद्ध होकर कार्य करना चाहिए। 'विकसित भारत 2047' के संकल्प के साथ विकसित और सुपोषित गुजरात के निर्माण के लिए सभी से मिलकर काम करने का अनुरोध किया गया।

-:महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मनीषाबेन वकील:-

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मनीषाबेन वकील ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों को टेक्नोलॉजी से जोड़कर उन्हें अधिक सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्यभर की लगभग 55 हजार से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों को स्मार्ट मोबाइल फोन वितरित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिससे आंगनवाड़ी सेवाएं अधिक प्रभावी बनेंगी। उन्होंने आगे कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों द्वारा केंद्रों में आने वाले बच्चों का वजन मापना, पोषण संबंधी जानकारी एकत्र करना और 'पोषण ट्रैकर' एप्लिकेशन में डेटा अपलोड करने जैसे कार्य अब अधिक आसान और तेज हो जाएंगे। इससे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर लगातार निगरानी रखी जा सकेगी।

श्रीमती मनीषाबेन वकील ने आगे कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों को दिया जाने वाला टेक होम राशन (टीएचआर) सही तरीके से पहुंच रहा है या नहीं, तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को दी जाने वाली सहायता और किट से संबंधित जानकारी भी अब आसानी से प्राप्त की जा सकेगी।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी सुविधाओं को और मजबूत बनाने के लिए 360 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जिसके तहत नए आंगनवाड़ी भवन और सुविधाओं का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।

-:राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला:-

इस अवसर पर शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शहरी विकास के क्षेत्र में पूरे देश में नई दिशा मिली है। अहमदाबाद शहर के नागरिकों को अच्छी सड़कें, सुविधापूर्ण आधारभूत विकास और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में विकास कार्यों के लिए किसी भी प्रकार की आर्थिक कमी नहीं रहती। सरकार द्वारा लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। पहले के समय में महानगर पालिका के पास विकास के लिए सीमित संसाधन थे, लेकिन अब राज्य सरकार के सहयोग से शहरों में सड़क, पुल और अन्य आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ गरीबों के लिए आवास निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी किए गए हैं।

अहमदाबाद महानगर पालिका आयुक्त श्री बंछानिधि पाणी ने स्वागत भाषण में शहर के विकास कार्यों की जानकारी के साथ आगामी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

मुख्यमंत्री के करकमलों से अहमदाबाद की स्मृति ग्रंथ - कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया।

इस अवसर पर सांसद श्री हसमुखभाई पटेल, सांसद श्री दिनेशभाई मकवाणा, श्री नरहरि अमीन, महानगर पालिका प्रशासक श्री मुकेश कुमार, महिला एवं बाल विकास सचिव श्री राकेश शंकर, औडा के सीईओ श्री देवांग देसाई सहित स्थानीय विधायक, कई अग्रणी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 31 मार्च को साणंद में सेमीकंडक्टर ओएसएटी प्लांट का उद्घाटन करेंगे

▸▸ केन्स सेमीकॉन द्वारा साणंद में 3300 करोड़ रुपए के खर्च से प्लांट का निर्माण, भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को मिलेगी गति

▸▸ साणंद आज ग्लोबल मैप पर सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभर रहा है, यह दशक भारत के टेक फ्यूचर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 31 मार्च, 2026 को साणंद में केन्स सेमीकॉन की आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (ओएसएटी) सुविधा का शुभारंभ करेंगे।

भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इस प्रोजेक्ट को केंद्रीय कैबिनेट ने 23 सितंबर, 2024 को स्वीकृति दी थी। 3300 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से साणंद में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और अधिक मजबूत होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अनुसार, भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास से यह दशक टेक फ्यूचर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास के लिए काफी तेजी से काम हो रहा है। माइक्रोन प्लांट के शुभारंभ के बाद केन्स सेमीकॉन की ओएसएटी सुविधा के शुरू होने से स्थानीय आर्थिक विकास को और गति मिलेगी। ओएसएटी यानी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट में चिप की टेस्टिंग और पैकेजिंग करके उसे मार्केट तक पहुंचाने का काम पूरा किया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक, 31 मार्च को शुरू होने वाले इस प्लांट में प्रतिदिन 60 लाख चिप्स का उत्पादन होगा।

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की लंबी छलांग : बरसों का काम 900 दिनों में हुआ पूरा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 28 फरवरी, 2016 को माइक्रोन सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रोजेक्ट की गतिशीलता पर जोर देते हुए कहा, "जून 2023 में इस फैसिलिटी के लिए एमओयू साइन हुआ। सितंबर में शिलान्यास हुआ और आज फरवरी 2026 में कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो गया। दुनिया के विकसित देशों में भी ऐसी मंजूरियों और प्रक्रियाओं में वर्षों निकल जाते हैं, लेकिन भारत ने इस असंभव कार्य को केवल 900 दिनों में पूरा कर दिखाया है। जब नीयत साफ हो और निष्ठा देश के तेज विकास के प्रति हो, तब नीति भी स्पष्ट बनती है और निर्णयों में भी गति आ ही जाती है।"

साणंद : ऑटो हब से लेकर सेमीकंडक्टर हब तक

साणंद के औद्योगिक विकास में बहुत ही छोटी अवधि में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी, केन्स सेमीकॉन के साथ ही सीजी सेमी द्वारा भी यहां प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ऑटोमोबाइल हब के रूप में विख्यात साणंद, अब भारत के प्रथम चिप पैकेजिंग क्लस्टर और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है। ताइवान के सिंशु शहर और दक्षिण कोरिया के ग्योंगी शहर के समान भारत में साणंद सेमीकंडक्टर हब के रूप में विकसित हो रहा है।

हमारा लक्ष्य केवल फैक्ट्री स्थापित करने तक सीमित नहीं है : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने साफ तौर पर कहा, "हमारा लक्ष्य केवल एक फैक्ट्री स्थापित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण इकोसिस्टम बनाना है। भारत अब सेमीकंडक्टर की पूरी वैल्यू चेन पर फोकस कर रहा है, जिसमें डिजाइन इंजीनियर से लेकर मशीन निर्माता और लॉजिस्टिक्स तक के सभी स्तर शामिल हैं। 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' की घोषणा इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ेगा, वैसे-वैसे भारत में ही मटेरियल और कंपोनेंट्स की मांग बढ़ेगी, जो स्थानीय उद्योगों के लिए सबसे बड़ा अवसर बनेगी।"

भारत अब इस वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का बहुत ही अहम हिस्सा बन रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कोविड के मुश्किल दौर में बोए गए बीज आज वटवृक्ष बनकर फल दे रहे हैं और अब तक सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत 10 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, जिसमें चार प्रोजेक्ट गुजरात

ऊर्जा संकट में भारत बना सहारा: श्रीलंका में ब्लैकआउट के बीच 38,000 मीट्रिक टन पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति

नई दिल्ली। मध्य-पूर्व में जारी तनाव का असर अब छोटे देशों की अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर साफ दिखाई देने लगा है। Sri Lanka इस संकट से सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल हो गया है, जहां ईंधन की कमी ने हालात को गंभीर बना दिया है। ऐसे कठिन समय में India ने आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया है और 38,000 मीट्रिक टन पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति कर श्रीलंका को बड़ी राहत दी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह सहायता भारत की सहायक कंपनी Lanka IOC के माध्यम से भेजी गई। इसमें 20,000 मीट्रिक टन डीजल और 18,000 मीट्रिक टन पेट्रोल शामिल है। यह खेप 28 मार्च को कोलंबो पहुंची, जिससे वहां की बिगड़ती आपूर्ति व्यवस्था को कुछ हद तक स्थिर करने में मदद मिली। इस सहायता के पीछे कूटनीतिक स्तर पर हुई बातचीत भी महत्वपूर्ण रही। 24 मार्च को Anura Kumara Dissanayake और Narendra Modi के बीच हुई चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। यह घटनाक्रम भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति को भी मजबूत करता है, जिसके तहत वह अपने पड़ोसी देशों को संकट के समय प्राथमिकता के आधार पर सहायता प्रदान करता है। श्रीलंका में ऊर्जा संकट का असर अब जनजीवन पर गहराता जा रहा है। ईंधन की कमी के कारण देश के कई हिस्सों में ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। सरकार को मजबूरी में सख्त कदम उठाने पड़े हैं। सरकारी कार्यालयों में अब सप्ताह में केवल चार दिन काम हो रहा है, ताकि बिजली और ईंधन की खपत को कम किया जा सके।

सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी इस संकट से अछूती नहीं हैं। बसों और ट्रेनों की संख्या में कमी कर दी गई है, जिससे आम लोगों की दैनिक यात्रा प्रभावित हो रही है। बैंकिंग सेवाओं के समय में भी कटौती की गई है, जबकि कई निजी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए आंशिक रूप से 'वर्क फ्रॉम होम' व्यवस्था लागू कर दी है। ऊर्जा संकट से निपटने के लिए सरकार ने बिजली खपत में लगभग 25 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स को सीमित किया गया है और सरकारी दफ्तरों में ऊर्जा बचत के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं को दिन के समय ही चार्जिंग करने की सलाह दी गई है, ताकि रात के समय बिजली ग्रिड पर दबाव कम हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि श्रीलंका की मौजूदा स्थिति उसकी आयात पर अत्यधिक निर्भरता को दर्शाती है। देश के पास सीमित अवधि के लिए ही ईंधन भंडार उपलब्ध है, जिसके कारण वह अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति पर पूरी तरह निर्भर है।

सूरत : खाड़ी संकट की मार, दक्षिण गुजरात की इंडस्ट्री पर बढ़ा दबाव; सरकार से तुरंत राहत की मांग

Surat की तेज़ी से विकसित होती औद्योगिक पहचान आज एक नए वैश्विक संकट की चपेट में आती दिखाई दे रही है। खाड़ी क्षेत्र में बने युद्ध जैसे हालात अब केवल अंतरराष्ट्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि उनका सीधा असर भारत के औद्योगिक केंद्रों, खासकर दक्षिण गुजरात की अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। सूरत, जिसे देश की टेक्सटाइल और डायमंड कैपिटल के रूप में जाना जाता है, इस समय एक ऐसे आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है, जिसकी जड़ें हजारों किलोमीटर दूर खाड़ी देशों में चल रहे तनाव से जुड़ी हुई हैं।

29 मार्च 2026 को इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता Harsh Sanghavi ने की। इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विशेष रूप से Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry ने इस संकट के व्यापक प्रभावों को विस्तार से प्रस्तुत किया। चैंबर के प्रतिनिधिमंडल में प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी, वाइस प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला, ऑनरेरी ट्रेज़रर सीए मितिश मोदी और सेक्रेटरी पॉलिक देसाई शामिल थे, जिन्होंने विभिन्न सेक्टरों पर पड़ रहे प्रभावों को तथ्यों और आंकड़ों के साथ सामने रखा।

इस पूरे संकट का सबसे बड़ा असर कच्चे माल की लागत और सप्लाई चेन पर देखा जा रहा है। खाड़ी क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का एक प्रमुख केंद्र है, और वहां किसी भी प्रकार का तनाव सीधे तौर पर कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित करता है। तेल की कीमतों में हो रहे उतार-चढ़ाव ने सूरत की टेक्सटाइल, प्लास्टिक और केमिकल इंडस्ट्री के लिए लागत का संतुलन बिगाड़ दिया है। उत्पादन की लागत बढ़ रही है, लेकिन बाजार में मांग और कीमतों के बीच संतुलन बनाना उद्योगों के लिए चुनौती बनता जा रहा है।

इसके साथ ही रुपये की गिरावट और विदेशी मुद्रा में अस्थिरता ने आयात को और महंगा बना दिया है। जिन उद्योगों का कच्चा माल विदेशों से आता है, उन्हें अब पहले की तुलना में अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। इसका सीधा असर उनकी लाभप्रदता पर पड़ रहा है। कई छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए यह स्थिति अस्तित्व का संकट बनती जा रही है, क्योंकि उनके पास लागत बढ़ने के बावजूद कीमत बढ़ाने की सीमित क्षमता होती है।

इंडस्ट्रियल गैस की सप्लाई में आई बाधा ने उत्पादन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावित किया है। कई फैक्ट्रियां जो निरंतर गैस सप्लाई पर निर्भर हैं, उन्हें उत्पादन घटाने या अस्थायी रूप से बंद करने तक की नौबत आ रही है। यह स्थिति केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे हजारों श्रमिकों के रोजगार पर भी असर पड़ रहा है।

श्रमिक वर्ग की स्थिति इस संकट में सबसे अधिक संवेदनशील बन गई है। लेबर कॉलोनियों में एलपीजी सिलेंडर की कमी के कारण उनके दैनिक जीवन पर असर पड़ा है। खाना बनाने जैसी बुनियादी जरूरतों में कठिनाई आने लगी है, जिसके कारण कई श्रमिक अपने गृह राज्यों की ओर लौटने लगे हैं। यदि यह प्रवृत्ति बढ़ती है, तो उद्योगों के सामने श्रमिकों की कमी एक बड़ी समस्या बन सकती है, जिससे उत्पादन और अधिक प्रभावित होगा।

सूरत का हीरा उद्योग, जो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान रखता है, इस संकट से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। दुबई और एंटवर्प जैसे अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग हब, जहां से हीरों का बड़ा व्यापार होता है, वहां उत्पन्न बाधाओं के कारण एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है। तैयार माल का स्टॉक अटक गया है, जिससे नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) की समस्या उत्पन्न हो रही है। यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही, तो छोटे व्यापारियों और कारीगरों के लिए गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है।

इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry ने सरकार के सामने कई महत्वपूर्ण सुझाव भी रखे हैं। इनमें बिना कस्टम ड्यूटी के री-इम्पोर्ट की अनुमति देना, निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पैकेज प्रदान करना और भारत को एक वैश्विक ट्रेडिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनाना शामिल है। चैंबर का मानना है कि यदि समय रहते ये कदम उठाए जाते हैं, तो उद्योगों को इस संकट से उबरने में मदद मिल सकती है।

बैठक के दौरान Harsh Sanghavi ने उद्योग प्रतिनिधियों की चिंताओं को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस कठिन समय में उद्योगों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही व्यावहारिक और प्रभावी कदम उठाएगी, ताकि उद्योगों को राहत मिल सके और आर्थिक गतिविधियां सामान्य हो सकें।

इस पूरे घटनाक्रम को यदि व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी परस्पर जुड़ी हुई है। एक क्षेत्र में उत्पन्न संकट का असर हजारों किलोमीटर दूर स्थित उद्योगों पर भी पड़ सकता है। Surat का यह अनुभव इसी वैश्विक जुड़ाव की एक सजीव मिसाल है।

आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार कितनी तेजी से राहत उपाय लागू करती है और वैश्विक स्तर पर परिस्थितियां किस दिशा में जाती हैं। यदि हालात जल्दी सुधरते हैं, तो उद्योगों को राहत मिल सकती है, लेकिन यदि संकट लंबा खिंचता है, तो दक्षिण गुजरात की इंडस्ट्री के लिए यह एक लंबी और कठिन परीक्षा साबित हो सकती है।

सूरत : मिडिल ईस्ट तनाव के बीच इंडस्ट्री अलर्ट, हाई-लेवल मीटिंग में गैस सप्लाई और वर्कर्स के इंतज़ाम पर बड़ा फैसला

Surat। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे तौर पर दक्षिण गुजरात की इंडस्ट्री और श्रमिक व्यवस्था पर दिखने लगा है। इसी संवेदनशील स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने तेजी से एक्शन लेते हुए सूरत में हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग आयोजित की, जिसमें उद्योग, प्रशासन और सप्लाई सिस्टम से जुड़े सभी प्रमुख पक्षों को एक मंच पर लाया गया। यह महत्वपूर्ण बैठक Harsh Sanghavi की अध्यक्षता में सूरत के ICCC सेंटर में आयोजित की गई। इसमें अंकलेश्वर, वापी, भरूच, दहेज और पांडेसरा जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य था—किसी भी संभावित संकट से पहले तैयारी को मजबूत करना और इंडस्ट्री के संचालन को निर्बाध बनाए रखना।

बैठक के दौरान सबसे अहम मुद्दा गैस सप्लाई का रहा। मिडिल ईस्ट क्षेत्र से ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने की आशंकाओं के बीच उद्योगों और आम नागरिकों के लिए गैस की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ रही थीं। इस पर Harsh Sanghavi ने स्पष्ट किया कि राज्य में PNG, LPG, पेट्रोल और डीज़ल जैसी सभी आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता है और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार सप्लाई पूरी तरह सुचारू है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन उपलब्ध हैं, वहां LPG पर निर्भर उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर PNG कनेक्शन में शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा, गैस पाइपलाइन के आसपास के क्षेत्रों में भी तेजी से कनेक्शन देने की योजना पर काम करने को कहा गया, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की सप्लाई बाधा का असर कम किया जा सके।

बैठक में Darshan Shah ने केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप LPG सप्लाई की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के लिए गैस की आपूर्ति नियमित रूप से जारी है और इसे और बेहतर बनाने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।

इस हाई-लेवल मीटिंग में प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें Mamta Verma, K. C. Sampat और Saurabh Pardhi शामिल थे। सभी अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित तैयारियों और चुनौतियों पर चर्चा की।

मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में Harsh Sanghavi ने विशेष रूप से श्रमिकों (वर्कर्स) को लेकर चल रही चिंताओं पर बात की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों के कारण कारीगरों में डर का माहौल बन रहा है, जिसे दूर करने के लिए सरकार और इंडस्ट्री बॉडीज़ मिलकर काम कर रही हैं।

उन्होंने बताया कि श्रमिकों के लिए भोजन और रहने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बड़े स्तर पर कम्युनिटी किचन और वेयरहाउस की व्यवस्था की गई है। पांडेसरा, वापी, अंकलेश्वर और दहेज जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में कारीगरों को न सिर्फ भोजन बल्कि अस्थायी आवास की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि वे बिना किसी भय के अपने काम को जारी रख सकें।

सरकार द्वारा एक और अहम कदम उठाते हुए वर्कर्स को 5 किलोग्राम के छोटे गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। इससे उन श्रमिकों को राहत मिलेगी, जो अस्थायी रूप से रह रहे हैं या जिनके पास नियमित गैस कनेक्शन नहीं है। इसके साथ ही Harsh Sanghavi ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि के भ्रामक या गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए भी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। हर जिले में विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो गैस सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी पर नजर रखेंगी। किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

सरकार और उद्योग जगत के संयुक्त प्रयासों का ही परिणाम है कि अब तक सूरत और आसपास के क्षेत्रों में 118 कम्युनिटी किचन शुरू किए जा चुके हैं। ये किचन हजारों श्रमिकों के लिए रोजाना भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे किसी भी प्रकार की मानवीय संकट की स्थिति बनने से रोका जा सके।

कुल मिलाकर, Surat में आयोजित यह हाई-लेवल मीटिंग केवल एक समीक्षा बैठक नहीं, बल्कि एक रणनीतिक पहल है, जिसका उद्देश्य संभावित संकट को पहले ही नियंत्रित करना है। मिडिल ईस्ट के हालात चाहे जैसे भी हों, राज्य सरकार और उद्योग जगत मिलकर यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि दक्षिण गुजरात की औद्योगिक धड़कन थमे नहीं और श्रमिकों का विश्वास बना रहे।

सताधार के पवित्र स्थल पर आत्मनिर्भरता की आरती : रोजाना 10 हजार श्रद्धालुओं का भोजन बायोगैस पर तैयार होता है

▸▸ सताधार धाम में गुजरात का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र कार्यरत है : यहां मौजूद एक हजार गायों से प्रतिदिन मिलने वाले 8 हजार किलो गोबर का उपयोग बायोगैस संयंत्र चलाने के लिए होता है

▸▸ वर्तमान में प्रतिदिन 85 घनमीटर की क्षमता वाले चार बायोगैस संयंत्र हैं जबकि दो और नए संयंत्र तैयार हो रहे हैं

▸▸ पिछले पांच वर्षों में राज्य में कुल 193 संस्थाओं में बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए

▸▸ इन सभी संयंत्रों की क्षमता प्रतिदिन 13,955 घनमीटर बायोगैस उत्पादन की है

▸▸ गुजरात ऊर्जा विकास निगम संस्थाओं को देता है सब्सिडी

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग में आत्मनिर्भर बन रहा है

गांधीनगर : गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध यात्राधाम संत आपा गीगा का स्थान सताधार धाम अपने संध्या आरती दर्शन के लिए विख्यात है। आपा गीगा का यह 'पवित्र स्थल' अब वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया है। सताधार स्थान संध्या आरती की पवित्र ज्वाला के साथ-साथ आत्मनिर्भरता की ज्वाला भी प्रज्वलित कर रहा है।

सताधार धाम में गुजरात का सबसे अधिक क्षमता वाला बायोगैस संयंत्र कार्यरत है। वर्तमान में यहां दैनिक 85 घनमीटर की क्षमता वाले चार बायोगैस संयंत्र चालू हैं और दो और (दैनिक 85 घनमीटर) नए बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। सताधार स्थान में एक हजार गायें हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि यहां श्रद्धालुओं के लिए एक विशाल अन्नक्षेत्र चलाया जाता है, जहां रोजाना औसतन 10,000 लोगों को सात्विक भोजन-प्रसाद मिलता है। इस रसोई को चलाने के लिए केवल बायोगैस का उपयोग किया जाता है। बायोगैस उत्पन्न करने के लिए रोजाना 8 हजार किलो गोबर का उपयोग होता है।

संस्था के प्रबंधकों ने बताया कि जब बायोगैस की व्यवस्था नहीं थी, तब रसोई बनाने के लिए लकड़ी के चूल्हे का उपयोग किया जाता था, जिसके लिए रोजाना 800 से 900 किलो लकड़ी का इस्तेमाल होता था। वहीं, जब रसोई के लिए सिलेंडर का इस्तेमाल होता था, तब रोजाना औसतन 10 से 15 सिलेंडर की

खपत होती थी।

सताधार के महंत विजयबापू ने बताया, "हम यहां खाना पकाने के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं और रसोई बनाने के लिए केवल बायोगैस का ही उपयोग करते हैं। इसके अलावा, बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली स्लरी का उपयोग संस्था की कृषि गतिविधियों में जैविक खाद के रूप में किया जाता है।"

गुजरात सरकार के गुजरात ऊर्जा विकास निगम (जीईडीए) द्वारा 'संस्थागत बायोगैस प्लांट योजना' के अंतर्गत संस्थाओं को बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। सताधार धाम को भी इस सहायता का लाभ मिला है।

गुजरात में स्थित गौशालाओं, पिंजरापोलों, शैक्षणिक संस्थानों और चेरिटेबल ट्रस्टों के पास बड़े पैमाने पर पशुधन के साथ ही कृषि अवशेष और रसोई का कचरा उपलब्ध होता है। इन सभी जैविक पदार्थों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में (एनेरोबिक प्रक्रिया के माध्यम से) बायोगैस में परिवर्तित किया जाता है, जो खाना पकाने के लिए एक किफायती ईंधन प्रदान करता है। साथ ही, इस प्रक्रिया के बाद मिलने वाला उप-उत्पाद स्लरी उत्तम नाइट्रोजन युक्त जैविक खाद के रूप में कृषि में उपयोगी सिद्ध होता है। गुजरात सरकार के गुजरात ऊर्जा विकास निगम द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के लिए संस्थाओं को सब्सिडी दी जाती है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।

राज्य में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन देने तथा गौशाला, पिंजरापोलों, शैक्षणिक एवं अन्य संस्थानों में उत्पन्न होने वाले जैविक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से सदुपयोग करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संस्थागत बायोगैस संयंत्र की स्थापना की विशेष योजना लागू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य संस्थाओं को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है।

इस योजना के अंतर्गत 25, 35, 45, 60 और 85 घनमीटर क्षमता वाले संयंत्र के लिए सहायता दी जाती है। राज्य सरकार गैर-लाभकारी संस्थानों को 50 फीसदी तक की सहायता देती है, ताकि अधिक से अधिक संस्थाएं स्वच्छ ऊर्जा और जैविक कृषि की दिशा में आगे बढ़ सके।

राज्य में 193 से अधिक संस्थागत बायोगैस संयंत्र कार्यरत

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संस्थागत बायोगैस योजना के तहत कुल 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिनमें से लगभग 60 संस्थागत बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 15 एजेंसियों को सूचीबद्ध किया गया है। इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान, पिछले पांच वर्षों में कुल 193 संस्थाओं में बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनकी कुल क्षमता दैनिक 13,955 घनमीटर है। आगामी वर्ष 2026-27 के लिए भी संस्थागत बायोगैस योजना के अंतर्गत कुल 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 60 बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की योजना है।

नारणपुरा से साइंस सिटी की ओर जाने वाले मार्ग पर सताधार चार रास्ते पर लगभग 90 करोड़ रुपए के खर्च से फोरलेन फ्लाईओवर ब्रिज बनने से वाहन चालकों में खुशी का माहौल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से सताधार फोरलेन फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण किया गया

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से रविवार को अहमदाबाद के घाटलोडिया क्षेत्र में स्थित सताधार जंक्शन पर नवनिर्मित फोरलेन फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री श्री नव-लोकार्पित फ्लाईओवर ब्रिज पर से गुजरकर अपने अगले कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। नारणपुरा से सोला साइंस सिटी की ओर जाने वाले मार्ग पर सताधार चार रास्ते पर अहमदाबाद महानगर पालिका द्वारा लगभग 90 करोड़ रुपए के खर्च से फोरलेन फ्लाईओवर ब्रिज बनाया गया है। 936 मीटर लंबाई और 16.60 मीटर चौड़ाई वाला यह फ्लाईओवर ब्रिज बनने से ट्रैफिक की समस्या में काफी बड़ी राहत मिलेगी। सताधार फ्लाईओवर ब्रिज के

लोकार्पण से वाहन चालकों में खुशी का माहौल देखा गया।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री द्वारा सताधार जंक्शन पर फ्लाईओवर बनाने का सुझाव दिया गया था तथा ओवरब्रिज के लिए 'स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना' अंतर्गत अनुदान आवंटित किया गया था।

इस अवसर पर शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला, स्थानीय विधायक, अहमदाबाद महानगर पालिका के प्रशासक श्री मुकेश कुमार, आयुक्त श्री बंछानिधि पाणी, उच्च अधिकारी, अहमदाबाद महानगर पालिका के पूर्व पदाधिकारी तथा स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

700 अरब डॉलर से नीचे आया विदेशी मुद्रा भंडार: एक हफ्ते में 11.41 अरब डॉलर की गिरावट, क्या हैं इसके संकेत

नई दिल्ली। India की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है, जहां देश का विदेशी मुद्रा भंडार करीब दो महीने बाद फिर से 700 अरब डॉलर के स्तर से नीचे आ गया है। Reserve Bank of India (आरबीआई) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, 20 मार्च 2026 को समाप्त सप्ताह में कुल विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 698.35 अरब डॉलर रह गया, जबकि इससे पिछले सप्ताह यह 709.76 अरब डॉलर था। इस तरह महज एक सप्ताह में 11.41 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट ऐसे समय आई है, जब कुछ ही हफ्ते पहले फरवरी के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 728.5 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा था। उस समय इसे देश की आर्थिक मजबूती का संकेत माना जा रहा था, लेकिन उसके बाद से इसमें लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ताजा आंकड़ों ने एक बार फिर इस बात की ओर ध्यान खींचा है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां और बाजार की हलचलें किस तरह घरेलू वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हैं।

इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण स्वर्ण भंडार यानी गोल्ड रिजर्व के मूल्य में कमी को माना जा रहा है। आरबीआई के अनुसार, समीक्षा अवधि के दौरान गोल्ड रिजर्व का मूल्य लगभग 13.5 अरब डॉलर घटकर 117.2 अरब डॉलर रह गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर इसके मूल्यांकन पर पड़ा है। चूंकि विदेशी मुद्रा भंडार में सोना भी एक महत्वपूर्ण घटक होता है, इसलिए इसकी कीमत में गिरावट कुल भंडार को सीधे प्रभावित करती है।

इसके अलावा, विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए आरबीआई द्वारा बाजार में डॉलर की बिक्री भी इस गिरावट का एक कारण हो सकती है। जब रुपये पर दबाव बढ़ता है, तो केंद्रीय बैंक डॉलर बेचकर बाजार में संतुलन बनाने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर अस्थायी रूप से घट सकता है।

आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार में होने वाले बदलाव कई कारकों पर निर्भर करते हैं। इनमें विदेशी निवेश का प्रवाह, वैश्विक वित्तीय बाजारों की स्थिति, डॉलर के मुकाबले रुपये की मजबूती या कमजोरी, और केंद्रीय बैंक की नीतिगत हस्तक्षेप शामिल हैं। हाल के समय में वैश्विक स्तर पर अस्थिरता बढ़ी है, जिसका असर भारत जैसे उभरते बाजारों पर भी पड़ा है। हालांकि, इस गिरावट के बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा स्तर अभी भी काफी मजबूत है। 698 अरब डॉलर का भंडार देश की कई महीनों की आयात जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है।

नया रूप, नई पहचान-जेतलसर रेलवे स्टेशन का 16.32 करोड़ की लागत का उन्नयन कार्य स्वीकृत

यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा एवं आधुनिक रेलवे अवसंरचना के विकास को प्राथमिकता देते हुए पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा जेतलसर रेलवे स्टेशन के व्यापक उन्नयन कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन एवं प्रयासों से इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 16.32 करोड़ की लागत 27.03.2026 को स्वीकृत की गई है, जो बजट वर्ष 2025-26 के अंतर्गत अनुमोदित है।

उल्लेखनीय है कि स्टेशन पर पूर्व में उपलब्ध फुट ओवर ब्रिज, जो प्लेटफॉर्म संख्या 1 एवं 2/3 को जोड़ता था, का सफलतापूर्वक विस्तार करते हुए प्लेटफॉर्म संख्या 4/5 तक जोड़ दिया गया है। विस्तारित फुट ओवर ब्रिज को दिनांक 16 मार्च, 2026 से यात्रियों के उपयोग हेतु खोल दिया गया है, जिससे आवागमन और अधिक सुगम एवं सुरक्षित हो गया है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वीकृत उन्नयन कार्यों के अंतर्गत स्टेशन पर निम्नलिखित प्रमुख सुविधाओं का विकास किया जाएगा—

स्टेशन के परिसंचारी क्षेत्र में सुधार के साथ सार्वजनिक एवं स्टाफ पार्किंग का विस्तार

स्टेशन भवन के अग्रभाग का सौंदर्यीकरण तथा आगमन/प्रस्थान प्लाजा का निर्माण

प्लेटफॉर्म 2/3 पर स्थित वेटिंग रूम, लॉबी एवं आरपीएफ पोस्ट का प्लेटफॉर्म 1 पर आधुनिक भवन में स्थानांतरण (विद्युत एवं दूरसंचार कक्ष सहित)

प्लेटफॉर्म 1 पर सफाई, वाणिज्यिक एवं यांत्रिक कर्मियों हेतु पृथक कक्षों का निर्माण

विभिन्न प्लेटफार्मों पर नए कवरशेड की स्थापना

प्लेटफॉर्म 2/3 एवं 4/5 पर दिव्यांगजन अनुकूल आधुनिक शौचालय ब्लॉकों का निर्माण

यात्रियों के लिए पर्याप्त पेयजल बूथ एवं वाटर कूलर की व्यवस्था

स्टेशन परिसर में उन्नत एवं पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था

प्लेटफॉर्म 2 एवं 3 पर इलेक्ट्रॉनिक कोच गाइडेंस सिस्टम की स्थापना

इन सभी विकास कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत जेतलसर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को आधुनिक, सुरक्षित एवं अधिक सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्राप्त होगा। यह परियोजना क्षेत्रीय विकास एवं रेल सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।

गुजरात में रेल विकास को मिली नई गति :

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 891 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण – 31 मार्च, 2026

भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार और क्षेत्रीय संतुलित विकास के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दिनांक 31 मार्च, 2026 को गुजरात में 891 करोड़ की विभिन्न रेल परियोजनाओं का लोकार्पण एवं राष्ट्र को समर्पण करेंगे।

इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा खेड़ब्रह्मा – हिम्मतनगर – अहमदाबाद (असारवा) के बीच नई ट्रेन सेवा का शुभारंभ एवं खेडब्रह्मा-हिम्मतनगर रेल लाइन का लोकार्पण तथा गांधीधाम–आदीपुर रेल लाइन के मल्टी-ट्रैकिंग एवं कानालुस–जामनगर रेल लाइन के दोहरीकरण का राष्ट्र को समर्पण किया जाएगा, जिससे उत्तर गुजरात और राज्य के केंद्रीय भाग के बीच तेज, सुलभ और विश्वसनीय परिवहन व्यवस्था स्थापित होगी।

रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक विस्तार एवं आधुनिकीकरण

ये परियोजनाएं केवल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के लिए प्रेरक सिद्ध होंगी। बेहतर रेल कनेक्टिविटी से व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

लोकार्पित होने वाली प्रमुख रेल परियोजनाएं

नई ट्रेन सेवा : क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा

खेड़ब्रह्मा से हिम्मतनगर होते हुए अहमदाबाद (असारवा) तक शुरू होने वाली नई ट्रेन सेवा आम जनता के लिए दैनिक यात्रा को सरल बनाएगी। विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और मरीजों के लिए शहर तक आवागमन अधिक सुविधाजनक और किफायती होगा। इससे ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों का सीधा संपर्क बड़े शहरों से होगा, जिससे जीवन स्तर में सुधार आएगा और स्थानीय व्यापारियों को नए बाजार उपलब्ध होंगे।

खेड़ब्रह्मा – हिम्मतनगर रेल लाइन (55 किमी)

482 करोड़ की लागत से निर्मित इस नई रेल लाइन से साबरकांठा क्षेत्र को सीधी रेल सुविधा प्राप्त होगी। अब लोग अहमदाबाद से नाना अंबाजी तक कम समय में और किफ़ायती किराए पे आसानी से पहुंच सकेंगे। किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक शीघ्र पहुंचाने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। यह परियोजना स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी तथा क्षेत्रीय विकास को गति प्रदान करेगी।

गांधीधाम – आदिपुर रेलखंड का मल्टीट्रैकिंग (11 किमी)

152 करोड़ की लागत से निर्मित इस नई रेल लाइन से मालगाड़ियों की आवाजाही सुगम होगी। कांडला पोर्ट एवं आसपास के उद्योगों को माल परिवहन में तेजी मिलेगी, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ट्रेनों की समयपालन में सुधार होगा और यात्रियों को कम असुविधा होगी। विशेष रूप से नमक, कंटेनर, उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद एवं कोयले के परिवहन में गति और दक्षता बढ़ेगी, जिससे लॉजिस्टिक्स प्रणाली और मजबूत होगी।

कानालुस – जामनगर रेलखंड का दोहरीकरण (27 किमी)

257 करोड़ की लागत से पूर्ण इस परियोजना के तहत अब एक ही मार्ग पर दो ट्रैक उपलब्ध हो गए हैं, जिससे ट्रेनों के संचालन में विलंब कम होगा। यात्रियों को समय पर ट्रेन मिलेगी और यात्रा अधिक आरामदायक बनेगी। मालगाड़ियों की गति में वृद्धि से व्यापार को भी लाभ होगा। यह परियोजना जामनगर एवं आसपास के क्षेत्रों के विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा भविष्य में नई ट्रेनों के संचालन के लिए भी सहायक सिद्ध होगी।

समावेशी विकास की दिशा में सशक्त कदम

भारतीय रेलवे द्वारा की जा रही ऐसी पहलें देश के अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हुए "सबका साथ, सबका विकास" के सिद्धांत को साकार करती हैं। ये परियोजनाएं राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी तथा भारत को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में माइलस्टोन साबित होंगी। प्रधानमंत्री द्वारा इन परियोजनाओं का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा।

वडोदरा – नागदा खंड पर 'कवच' प्रणाली की आज कमीशनिंग

रेल संरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करते हुए, पश्चिम रेलवे के सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग द्वारा वडोदरा–नागदा खंड पर स्वदेशी 'कवच' प्रणाली की आज, 30 मार्च, 2026 को कमीशनिंग की जायेगी। यह कार्य नवीनतम संस्करण 4.0 मानकों के अनुसार किया गया है, जो इस उच्च घनत्व वाले मार्ग पर एक महत्वपूर्ण तकनीकी उन्नयन है।

कवच प्रणाली को कुल 224.51 रूट किलोमीटर (Rkm) में लागू किया जायेगा, जिसमें वडोदरा से मंगल महुड़ी (122.5 Rkm) एवं पंचपिपलिया से नागदा (102.01 Rkm) खंड शामिल हैं। पश्चिम रेलवे द्वारा कवच प्रणाली का विस्तार लगातार किया जा रहा है। 30 जनवरी 2026 को 344 किलोमीटर लंबे वडोदरा–विरार खंड पर कवच 4.0 का सफल कमीशनिंग किया गया था। इससे पहले, दिसंबर 2025 में वडोदरा–अहमदाबाद खंड पर भी कवच प्रणाली लागू की जा चुकी है। स्वदेशी 'कवच' प्रणाली मानव त्रुटियों को कम करते हुए आवश्यक परिस्थितियों में स्वतः हस्तक्षेप करती है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना में उल्लेखनीय कमी आती है।

पश्चिम रेलवे आधुनिक एवं स्वदेशी तकनीकों को अपनाकर सुरक्षित, दक्ष एवं भविष्य उन्मुख रेल नेटवर्क के निर्माण हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है।

सूरत मेट्रो ने पकड़ी रफ्तार: ड्रीम सिटी–अलथान रूट पर शुरू हुआ ट्रायल रन, शहर को मिलेगी ट्रैफिक से राहत

सूरत। Surat शहर के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित मेट्रो परियोजना अब जमीन पर साकार होती नजर आ रही है। आधुनिक शहरी परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ड्रीम सिटी से अलथान टेनेमेंट स्टेशन के बीच 8.5 किलोमीटर लंबे रूट पर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक पहल के साथ सूरत अब उन चुनिंदा भारतीय शहरों की कतार में शामिल होने जा रहा है, जहां मेट्रो नेटवर्क नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए तैयार है।

इस ट्रायल रन के शुरू होने से न केवल परियोजना की प्रगति का संकेत मिला है, बल्कि शहरवासियों में भी नई उम्मीद जागी है। लंबे समय से चल रहे निर्माण कार्य और उससे पैदा हुई ट्रैफिक समस्याओं के बीच यह एक राहत भरी खबर के रूप में सामने आई है।

मेट्रो अधिकारियों के अनुसार, इस रूट पर सभी प्रमुख तकनीकी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। वायडक्ट (उच्च स्तरीय पुल), ट्रैक बिछाने का काम और ट्रैक्शन पावर के लिए तीसरी रेल की व्यवस्था पूरी तरह

तैयार हो चुकी है। यह तीसरी रेल प्रणाली मेट्रो ट्रेन को निर्बाध और तेज गति से संचालित करने में मदद करती है।

इस कॉरिडोर पर कुल सात स्टेशनों का ढांचा तैयार कर लिया गया है। हालांकि, इन स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट गेट, एस्केलेटर, लिफ्ट और अन्य फिनिशिंग कार्य तेजी से जारी हैं। निर्माण एजेंसियों का लक्ष्य है कि सभी कार्य समय सीमा के भीतर पूरे कर लिए जाएं, ताकि मेट्रो सेवा जल्द से जल्द आम जनता के लिए शुरू की जा सके।

ट्रायल रन के दौरान मेट्रो ट्रेन को लगभग 500 घंटे तक चलाया जाएगा। इस दौरान विभिन्न तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं की गहन जांच की जाएगी। इसके बाद Research Designs and Standards Organisation (आरडीएसओ) और Commissioner of Metro Railway Safety (सीएमआरएस) द्वारा निरीक्षण और वेरिफिकेशन किया जाएगा। इन दोनों संस्थाओं की मंजूरी के बाद ही मेट्रो को व्यावसायिक संचालन के लिए हरी झंडी मिलेगी।

पूरा सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट कुल 40.45 किलोमीटर लंबे दो प्रमुख कॉरिडोर पर विकसित किया जा रहा है। पहला कॉरिडोर ड्रीम सिटी से सरथाना तक फैला हुआ है, जिसे 'डायमंड कॉरिडोर' कहा जाता है, जबकि दूसरा कॉरिडोर सारोली से भेंसान तक 'टेक्सटाइल कॉरिडोर' के नाम से जाना जाता है। ये दोनों कॉरिडोर शहर के प्रमुख औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों को जोड़ेंगे, जिससे आवागमन आसान और तेज हो जाएगा।

लंबे समय से चल रहे निर्माण कार्य के कारण सूरत के नागरिकों को भारी ट्रैफिक जाम और असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब मेट्रो के संचालन से इस समस्या में काफी हद तक कमी आने की उम्मीद है। मेट्रो एक तेज, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्प के रूप में सामने आएगी।

अधिकारियों का दावा है कि जून 2026 तक मेट्रो सेवा का पहला चरण ड्रीम सिटी–सरथाना रूट पर शुरू किया जा सकता है। यह समयसीमा परियोजना की गति और ट्रायल रन की सफलता पर निर्भर करेगी।

सूरत मेट्रो की एक खास बात इसका आधुनिक और अत्याधुनिक तकनीक से लैस होना है। इस मेट्रो में तीन कोच होंगे और यह ड्राइवरलेस सिस्टम से संचालित होगी। इसकी अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे यात्रियों को तेज और समयबद्ध सेवा मिल सकेगी। सुरक्षा के लिहाज से भी इसमें कई उन्नत सुविधाएं दी गई हैं। सभी कोचों में सीसीटीवी कैमरे, फायर डिटेक्शन सिस्टम और रियल-टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था होगी। इससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई संभव होगी।

मेट्रो के किराए को लेकर भी प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार, 1 से 3 स्टेशनों तक यात्रा के लिए 10 और 20 या उससे अधिक स्टेशनों के लिए 40 तक किराया निर्धारित किया जा सकता है। हालांकि, अंतिम किराया मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद ही तय किया जाएगा।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। शहर में आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए मेट्रो ट्रायल रन की टाइमिंग को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से पहले इस परियोजना को गति देना एक रणनीतिक कदम हो सकता है।

हालांकि, आम नागरिकों के लिए यह राजनीति से परे एक बड़ी राहत की खबर है। सूरत जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में मेट्रो सेवा का शुरू होना ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक नई दिशा देगा।

कुल मिलाकर, Surat मेट्रो का ट्रायल रन न केवल एक तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि यह शहर के भविष्य की नई तस्वीर भी पेश करता है। आने वाले समय में यह परियोजना सूरत को एक स्मार्ट और आधुनिक शहर के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जहां यातायात की समस्याएं कम होंगी और जीवन अधिक सुगम होगा।